

[2023] 4 एस. सी. आर. 798

कनिमोझी करुणानिधि

वी.

ए. शांतना कुमार और ओआरएस

(2023 की सिविल अपील संख्या 3411)

04 मई, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 83 (1) (ए)-आयोजित परिणामों का गैर-अनुपालन: धारा 83 (1) (ए) आदेश देती है कि

एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होगा जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है- यदि किसी चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो उसे केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता है, क्योंकि मामला आर के खंड (ए) द्वारा कवर किया जाएगा। 11 सी. पी. सी. की धारा 7-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या 7, आर. 11 (ए)।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस। 100 (1) (घ) (iv), 83 (i) (क) प्रत्यर्थी सं। 1 चुनाव याचिका दायर की गई

यह घोषणा करते हुए कि लोकसभा चुनाव में थूथुकुडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 36 नंबर से अपीलकर्ता द्वारा वापस लिए गए उम्मीदवार का चुनाव अमान्य था और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए-आग्रह किया गया कि आधार यह था कि अपीलकर्ता ने भुगतान के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की थी।

प्रपत्र सं. में शपथ पत्र में उसके जीवनसाथी (अपीलार्थी के अनुसार एक विदेशी नागरिक) का आयकर। 26 - याचिकाकर्ता ने खारिज करने की मांग की चुनाव याचिका, आवेदन खारिज-आयोजित: यदि प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने पति या पत्नी के पैर को दबा दिया था और विदेश में अपने पति या पत्नी के आयकर का भुगतान न करने के बारे में भी, तो यह प्रत्यर्थी की ओर से चुनाव याचिका में राज्य के लिए अनिवार्य था कि भारत में अपीलार्थी के पति या पत्नी का पैर क्या था जिसे उसने दबा दिया था और उक्त प्रपत्र संख्या 26 में उसके पति के बारे में दिए गए अन्य विवरण कैसे अधूरे या झूठे थे-बिना किसी आधार के केवल गंजे और अस्पष्ट आरोप पर्याप्त अनुपालन नहीं होंगे।

कार्रवाई का कारण यू / s.100 (1) (d) (iv)-चुनाव याचिका खारिज

798 कनिमोझी करुणानिधि बनामा ए. शांतना कुमार

Or.VII, आर. 11 (ए), सी. पी. सी. आर/डब्ल्यू. एस. 83 (i) (क)-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया-चुनाव संचालन नियम 1961-rr। 4 , 4 ए.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 324-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

या 7, आर. 11 (ए)।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-चुनाव का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार और चुनाव पर विवाद करने का अधिकार -

आयोजित किया गया: चुनाव का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून का अधिकार-यह विशुद्ध रूप से एक वैधानिक अधिकार है-इसी तरह, निर्वाचित होने का अधिकार और चुनाव पर विवाद करने का अधिकार भी वैधानिक सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार हैं-एक चुनाव याचिका सामान्य कानून में कार्रवाई नहीं है, न ही निष्पक्षता में-यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है जिसका उपयोग इसे बनाने वाले कानून के अनुसार किया जाता है-चुनाव याचिका एक गंभीर मामला है, इसे हल्के में या काल्पनिक तरीके से नहीं माना जा सकता है और न ही इसे उस व्यक्ति को दिया जाता है जो इसे परेशान करने वाले उद्देश्य के लिए एक हैंडल के रूप में उपयोग करता है-भारत का संविधान-भाग-XV।

शब्द और वाक्यांश "भौतिक तथ्य"-क्या होता है -

चर्चा-जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 83 (1) (ए)।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 83 (1) (ए) में कहा गया है कि एक चुनाव याचिका में सामग्री का एक संक्षिप्त विवरण होगा।

जिन तथ्यों पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। यदि किसी चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो उसे केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता है, क्योंकि मामला संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) के दायरे में आएगा। भौतिक तथ्य ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए एक आधार प्रदान करेंगे और कार्रवाई का कारण बनेंगे, यह वह हर तथ्य है जिसे वादी/याचिकाकर्ता के लिए साबित करना आवश्यक होगा, यदि अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए इसे पार किया जाता है। एक भौतिक तथ्य को छोड़ देने से कार्रवाई का एक अधूरा कारण बन जाएगा और शिकायत का बयान खराब हो जाएगा। भौतिक तथ्यों का अर्थ है तथ्यों का पूरा समूह जो कार्रवाई का एक पूर्ण कारण होगा। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और यदि आवश्यक हो तो नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रतिपादन भी शामिल होगा। चुनाव को अमान्य घोषित कराने के लिए

आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत, चुनाव याचिकाकर्ता को प्रावधानों का पालन न करने के कारण यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

संविधान या अधिनियम या बनाए गए किसी भी नियम या आदेश [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में या काल्पनिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है और न ही इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसे परेशान करने वाले उद्देश्य के लिए एक हैंडल के रूप में उपयोग करता है। एक चुनाव याचिका संक्षेप में हो सकती है आदेश VII सी. पी. सी. के नियम 11 के खंड (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्रवाई के अपूर्ण कारण की ओर ले जाने वाले एकल भौतिक तथ्य को छोड़ने या भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त बयान शामिल करने में चूक, जिस पर याचिकाकर्ता कार्रवाई का कारण स्थापित करने के लिए निर्भर करता है, को अनिवार्य के साथ पढ़ा जाता है।

आर. पी. अधिनियम की धारा 83 द्वारा निर्धारित आवश्यकताएँ। [पैरा 28] [825 बी-एच; 826-ए]

1.2 चुनाव याचिकाकर्ता यानी प्रतिवादी ने भौतिक तथ्यों को बताए बिना बहुत गंजे और अस्पष्ट आरोप लगाए हैं।

भारत के संविधान या आर. पी. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन कैसे नहीं किया गया। यदि चुनाव याचिका में किए गए अभिकथनों को फॉर्म संख्या 26 में अपीलार्थी द्वारा वापस भेजे गए उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि

पति या पत्नी के पैन नंबर के बारे में मांगी गई जानकारी

अपीलार्थी, यह कहा गया है कि "पैन संख्या नहीं", "जीवनसाथी के. अरविंदन विदेशी नागरिकता"। "जिस वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम आयकर विवरणी दाखिल की गई है" के संबंध में मांगी गई जानकारी के खिलाफ, अपीलार्थी द्वारा अपने जीवनसाथी के बारे में दी गई जानकारी "लागू नहीं" है। अपीलार्थी ने अपने स्थायी खाता संख्या और आयकर विवरणी आदि दाखिल करने की स्थिति आदि के संबंध में और जहां भी लागू हो, अपने पति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करके प्रपत्र संख्या 26 के सभी कॉलम भर दिए हैं। यदि प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता के अनुसार, अपीलार्थी ने स्थायी खाते को दबा दिया था

अपने जीवनसाथी की संख्या और विदेश में अपने जीवनसाथी के आयकर का भुगतान न करने के बारे में भी, चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से यह बताना अनिवार्य था कि भारत में लौटे उम्मीदवार के जीवनसाथी की स्थायी खाता संख्या क्या थी जिसे उसने दबा दिया था और कैसे उक्त प्रपत्र संख्या 26 में उसके पति के बारे में दिए गए अन्य विवरण अधूरे या झूठे थे। बिना किसी आधार के केवल गंजे और अस्पष्ट आरोप पर्याप्त अनुपालन नहीं होंगे।

चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता।

[पारस 30,31] [826-जी-एच; 827-ए-डी] कनिमोझी करुणानिधि बनाम।

ए. शांतना कुमार

1.3 यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नामांकन पत्र के साथ फॉर्म 26 में एक हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक है

उक्त अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 4 ए के अनुसार उम्मीदवार। निर्वाचन अधिकारी को किसी भी नामांकन पर की गई आपत्तियों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, धारा 36 (2) में उल्लिखित आधारों पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसमें इस आधार पर भी शामिल है कि अधिनियम की धारा 33 के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता हुई है।

हालांकि, नामांकन पत्र की जांच के समय और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 26 में शपथ पत्र-वापस कर दिया गया।

उम्मीदवार, न तो कोई आपत्ति उठाई गई थी, न ही निर्वाचन अधिकारी ने नियमों की धारा 33 या नियम 4 ए का कोई चूक या गैर-अनुपालन पाया था। यह मानते हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता को अपीलार्थी द्वारा भरे गए प्रपत्र संख्या 26 को देखने का अवसर नहीं मिला था, जब उसने इसे रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया था, और यह मानते हुए कि रिटर्निंग अधिकारी ने अपीलार्थी के नामांकन पत्र की ठीक से जांच नहीं की थी, और यह मानते हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता को उक्त 34 अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत चुनाव याचिका दायर करके सवाल करने का अधिकार था, तब भी इसमें कोई भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं। आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत कार्रवाई का कारण बनने वाली याचिका। चुनाव याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बनने वाले भौतिक तथ्यों के अभाव में

उक्त अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv), चुनाव याचिका को आदेश VII नियम 11 (ए) सी. पी. सी. के तहत खारिज करने की आवश्यकता है। आर. पी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) के साथ। आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) में कहा गया है कि एक चुनाव याचिका में एक संक्षिप्त विवरण होगा।

भौतिक तथ्यों का विवरण जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है, और कौन से तथ्य कार्रवाई का कारण बनते हैं। इस तरह के तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रतिपादन भी शामिल होगा। एक एकल तथ्य को छोड़ देने से कार्रवाई का अधूरा कारण बन जाएगा। जहाँ तक वर्तमान याचिका का संबंध है, इस बारे में कोई दावा नहीं किया गया है कि संविधान या आर. पी. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेश के प्रावधानों का अनुपालन कैसे नहीं किया गया और इस तरह का अनुपालन कैसे नहीं किया गया।

चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया, ताकि चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत आधार आकर्षित किया जा सके। इस तरह के महत्वपूर्ण और बुनियादी तथ्यों को बताने में चूक ने याचिका को आदेश [2023] 4 एस. सी. के तहत खारिज करने के लिए उत्तरदायी बना दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. पी. 1951 की धारा 83 (आई) (ए) के साथ पढ़ा जाने वाला नियम 7, नियम 11 (ए) सी. पी. सी.। प्रत्यर्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका-चुनाव याचिका खारिज कर दी जाती है। [पारस 33,34] [827-एफ-एच; 828-ए-एफ]

एन. पी. पोद्दुस्वामी बनाम। निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल

निर्वाचन क्षेत्र और अन्य। 1952 (1) एस. सी. सी. 94; जगन नाथ बनाम

जसवंत सिंह और अन्य। ए. आई. आर 1954 एस. सी 210: [1954] एससीआर

892 ; भिकजी केशव जोशी और अन्न। बनाम वृजलाल नंदलाल

ब्रियानी और ओआरएस। ए. आई. आर 1955 एस. सी. 610 [1955] एस. सी. आर. 428;

- पीछा किया।

राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल 2009 (10) एससीसी 541:

[2009] 14 एससीआर 836; हरि शंकर जैन बनाम सोनिया

गांधी 2001 (8) एससीसी 233: [2001] 3 पूरक। एससीआर 38;

सामंत एन. बालकृष्ण और अन्न। बनाम जॉर्ज फर्नांडीज और

ओआरएस। 1969 (3) एससीसी 238: [1969] 3 एससीआर 603; का संघ

भारत बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ए. एन. आर.

2002 (5) एस. सी. सी. 294 [2002] 3 एस. सी. आर. 696; महादेव

सुकाजी शिवशंकर बनाम रामरतन बापू और अन्य। 2004 (7)

एस. सी. सी. 181 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 553; अनिल वासुदेव

सालगांवकर बनाम नरेश कुशाली शिंगांवकर 2009 (9)

एस. सी. सी 310: [2009] 14 एस. सी. आर. 10-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 14 एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

रा 7 (i.

[2001] 3 पूरक। एससीआर 38

उस पर भरोसा करें

रा 7 (i:

[1969] 3 एससीआर 603

उस पर भरोसा करें

रा 7 (ii)

[2002] 3 एससीआर 696

उस पर भरोसा करें

रा 8 (i.

[1954] एससीआर 892

पीछा किया।

रा 18

[1955] एससीआर 428

रा 18

[1964] एससीआर 573

पीछा किया।

पीछा किया।

रा 18

[2002] 3 एससीआर 696

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[2004] 3 पूरक। एससीआर 553

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2009] 14 एससीआर 10

उस पर भरोसा करें

पैरा 26 कनिमोझी करुणानिधि बनाम। ए. शांतना कुमार

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.3411

2023 .

2019 के ओ. ए. Nos.929 और 930 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 19.11.2019 से।

के साथ

2023 की सिविल अपील No.3412।

पी. विल्सन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. जोसेफ एरिस्टोटल एस, रिचर्डसन विल्सन, अपूर्व मल्होत्रा, सुश्री सपना आई पिल्लई, सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा, सुश्री प्रिया

अरस्तू, एड. अपीलार्थी के लिए।

एस. माकेश, एन. आई. रामचंद्रन, एल. आर. वेंकटेशन, अनूप प्रकाश अवस्थी, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अपर्णा सिंह, सुश्री साक्षी उपाध्याय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी ने दोनों अपीलों में (इसके बाद वापसी करने वाले उम्मीदवार के रूप में संदर्भित) विवादित व्यक्ति की वैधता को चुनौती दी है। मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा मूल आवेदन संख्या में पारित सामान्य आदेश दिनांक 19.11.2019। 929/2019 और चुनाव याचिका संख्या 3/2019 में अपीलार्थी द्वारा दायर 930/2019, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

3. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि 19.03.2019 पर अधिसूचना के अनुसार नामांकन आमंत्रित किए गए थे

17 वीं लोकसभा के चुनावों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किया गया, जो 18.04.2019 पर होने वाला है। अपीलार्थी ने चुनाव आचरण नियम 1961 (इसके बाद उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 4 ए के अनुसार प्रपत्र संख्या 26 में हलफनामे के साथ अपना नामांकन संख्या 36-थूथुकुडी लोकसभा संविधान से दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारी द्वारा 27.03.2019 पर की गई थी। चुनाव निर्धारित समय के अनुसार 18.04.2019 पर आयोजित किए गए थे, और अपीलार्थी को 23.05.2019 पर 3,47,209 मतों के अंतर से उक्त संख्या 36 थूथुकुडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया था।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. चुनाव याचिकाकर्ता/प्रतिवादी नं. 1 इसमें एक मतदाता होने का दावा करते हुए, चुनाव याचिका दायर की गई है। 3/2019 ऊँचे से पहले

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद आर. पी. अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 80, 80 ए, 100 (1) (डी) (iv) के तहत अदालत ने मांग की

यह घोषणा करते हुए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसार आयोजित लोकसभा चुनाव में 36, थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से लौटे उम्मीदवार, यानी अपीलार्थी का चुनाव अमान्य था और इस आधार पर अलग रखा जा सकता है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपने जीवनसाथी के आयकर के भुगतान के संबंध में मांगी गई जानकारी उनके द्वारा हलफनामे में प्रदान नहीं की गई थी-फॉर्म संख्या। 26 नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया, और इस प्रकार जानबूझकर दबा दिया गया और मतदाताओं को इसका खुलासा नहीं किया गया।

5. चुनाव याचिका के पैरा 5 से 9 में लगाए गए सटीक आरोप इस प्रकार हैं:

" 5. याचिकाकर्ता विनम्रता से प्रस्तुत करता है कि चुनाव नियम 1961 के संचालन के नियम 4 के तहत दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र को देखने के बाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जनता के बीच इसे प्रसारित करने के बाद, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि वह अपने जीवनसाथी के आयकर के भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रही थी, जिसका उल्लेख तमिल भाषा में "थुनिवर" के रूप में किया गया था, अर्थात् सिंगापुर के नागरिक अरविंदन, कॉलम में पैर संख्या, आयकर रिटर्न दाखिल करने के अंतिम वित्तीय वर्ष और प्रत्येक वर्ष के लिए आयकर रिटर्न में दिखाई गई कुल आय, रुपये 26 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के चुनाव आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी के पालन में लौटने वाले उम्मीदवार द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली तमिल भाषा "पोरुथु" में जो जानकारी दी जानी है और भारत के संविधान के प्रावधानों का पालन न करने पर लौटने वाले उम्मीदवार द्वारा उसका दमन किया जाना है, चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित होता है।

6. याचिकाकर्ता विनम्रता से प्रस्तुत करता है कि एस. नं. भाग 3-भाग बी में शपथ पत्र प्रपत्र 26 द्वितीय प्रत्यर्थी ने निर्वाचन क्षेत्र संख्या, नाम और राज्य के संबंध में जानकारी संख्या 36, थूथुकुडी, तमिलनाडु के रूप में प्रदान की थी, लेकिन जबकि भाग ए संख्या 2 में, वह एनीमोजी करुणानिधि बनाम।

ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

यह उल्लेख किया गया है कि उनका चुनावी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 चेपौक, तमिलनाडु है, जो नामांकन पत्र के अनुचित जमा करने को उजागर करता है।

7. याचिकाकर्ता विनम्रता से प्रस्तुत करता है कि दूसरे प्रत्यर्थी के असंवैधानिक कार्य के खिलाफ व्यथित होने के कारण, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता आयकर रिटर्न में घोषित किए गए लौटे उम्मीदवार के जीवनसाथी की आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित होता है, वह इस माननीय न्यायालय के समक्ष वापस किए गए उम्मीदवार के चुनाव की घोषणा करने का अनुरोध कर रहा है।

उम्मीदवार, दूसरा प्रत्यर्थी, थूथकुडी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 से शून्य के रूप में और उसी को अलग कर दिया।

8. याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि नामांकन पत्र, शपथ पत्र फॉर्म 26 के भुगतान के विवरण के बिना है

उनके पति या पत्नी (थुनाइवर) अर्थात् श्री अरविंदन, सिंगापुर के नागरिक के आयकर की राशि, हालांकि आयकर की राशि के भुगतान के संबंध में जानकारी भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांगी जाती है, ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जनता को जानकारी प्रदान की जा सके। इसके अलावा, यहां यह बताना उचित है कि विदेशों से आय सिंगापुर आयकर अधिनियम के तहत आयकर के अधीन है और प्रत्येक आयकर दाता को आय प्रदान की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा कर संदर्भ संख्या।

अपने पति या पत्नी (थुनाइवर) के आयकर के भुगतान के संबंध में अपने पति या पत्नी के आयकर के भुगतान के संबंध में यहां दूसरे प्रतिवादी द्वारा लौटी गई जानकारी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को सिंगापुर में आयकर प्राधिकरण को आयकर के भुगतान की पूरी जानकारी प्राप्त करने से रोकती है और इसका पालन करने पर गलत हलफनामा दाखिल करने का कारण बनती है। नियम "।

6. उक्त चुनाव याचिका में, अपीलार्थी/लौटे उम्मीदवार ने ओ. ए. सं. 929/2019 के अनुच्छेद 5 से 17 को रद्द करने की प्रार्थना की।

ओ. ए. नं. 930/2019 ने याचिका दायर की थी और इस आधार पर याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था कि चुनाव याचिका में निहित आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट और भौतिक तथ्यों के थे, और इसलिए [2023] 4 एस. सी. आर. की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त अधिनियम की धारा 81,83,86 और 100। यह भी माना गया था कि अनुच्छेद संख्या 5 चुनाव याचिका में से 17 में भौतिक तथ्य नहीं थे और कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने विवादित सामान्य आदेश के माध्यम से अपीलार्थी/लौटे उम्मीदवार द्वारा दायर दोनों मूल आवेदनों को खारिज कर दिया।

दलों के लिए विद्वान परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुतियाँ:

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. विल्सन

निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

उक्त अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) इसे सभी के लिए अनिवार्य बनाती है।

(i)

चुनाव याचिकाओं में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त बयान शामिल होना चाहिए, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है, हालांकि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता भौतिक तथ्यों का समर्थन करने में विफल रहा है और इसलिए चुनाव याचिका को सीमित रूप से खारिज किया जा सकता है।

के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखना

((ख)

राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल ', और हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी 2 के मामले में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन शामिल होगा-यदि आवश्यक हो तो एक नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रतिपादन भी, और इसके अभाव में, चुनाव याचिका उत्तरदायी है

अकेले उस जमीन पर खारिज कर दिया गया।

(iii) सामंत एन. बालकृष्ण और अन्न पर भरोसा करना। बनाम जॉर्ज

फर्नांडीज और Ors.³, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक भी भौतिक तथ्य का समर्थन करने में विफलता कार्रवाई के अधूरे कारण की ओर ले जाती है

और दावे का बयान खराब हो जाता है।

((iv) तत्काल मामले में, हालांकि प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपीलार्थी ने प्रपत्र संख्या 26 शपथ पत्र में तथ्यों को दबा दिया है, वह यह बताने में विफल रहा है कि कौन से तथ्यों को दबा दिया गया था, और कैसे संविधान या अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जिसने संविधान को भौतिक रूप से प्रभावित किया था।

चुनाव का परिणाम।

प्रत्यर्थी द्वारा दायर पूरी चुनाव याचिका आधारित है।

(v)

1 2009 (10) एस. सी. सी. 541 2 2001 (8) एस. सी. सी. 233 3 1969 (3) एस. सी.
सी. 238 ओझी करुणानिधि बनाम।

ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

भौतिक तथ्यों को अधिक बताए बिना अनुमान

विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) में निहित आधार के समर्थन में भौतिक तथ्य।

अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और देनदारियों के साथ-साथ अपने जीवनसाथी की संपत्ति और देनदारियों की आयकर की स्थिति का खुलासा करना आवश्यक है, यदि इस संबंध में कॉलम तथ्य स्थिति में लागू नहीं होते हैं, यह तथ्यों को दबाने के बराबर नहीं हो सकता है।

प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश एस. 1 प्रस्तुतियाँ कम करना:

अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और Anr.4 में निर्धारित कानून का उल्लंघन किया है, जिसमें न्यायालय ने चुनाव आयोग को उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया था।

नागरिकता की स्थिति।

अपीलार्थी, आय के संबंध में प्रश्न के उत्तर में उसके जीवनसाथी के कर देय ने "नहीं" का उल्लेख किया था। अपीलार्थी विदेश में अपने जीवनसाथी के आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति का खुलासा करने में विफल रही थी, जैसा कि खुलासा किया जाना आवश्यक था।

प्रपत्र संख्या 26 में। अपीलार्थी ने आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति और सिंगापुर में दी गई आयकर संदर्भ संख्या का खुलासा किए बिना उक्त प्रपत्र में बस इतना कहा था कि उसका पति या पत्नी विदेशी नागरिक है।

अपीलार्थी विदेश में अपने पति या पत्नी द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति के विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य थी और इसका खुलासा न करना तथ्यों को दबाने और वैधानिक नियमों का पालन न करने के समान था।

उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम।

अपने परिवार की वित्तीय स्थिति का खुलासा नहीं करके, अपीलार्थी ने मतदाताओं को अवसर से वंचित कर दिया था

वोट डालने के बारे में निर्णय लें।

पारदर्शिता की कमी और अप्रमाणिकता-प्रपत्र में तथ्यों का खुलासा संख्या 26 ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था।

4 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान और आर. पी. अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधान:

9. पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, कुछ का उल्लेख करना फायदेमंद होगा

भारत के संविधान और आर. पी. अधिनियम, 1951 में निहित प्रासंगिक प्रावधान।

प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और यह कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या अन्य आधारों पर ऐसी सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। उनमें से कोई भी। अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 संसद को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदनों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को, यदि संसद ने ऐसा विधान नहीं बनाया है, तो राज्य के विधानमंडल के सदनों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है और खंड (बी) विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के लिए किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई हो और ऐसी तरीके से जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाए।

11. जहाँ तक आर. पी. अधिनियम, 1951 का संबंध है, इसका उद्देश्य, जो इसके संक्षिप्त शीर्षक में परिलक्षित होता है, राज्यों के चुनावों के संचालन के लिए प्रावधान करना है। संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों के लिए, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, ऐसे चुनावों में या उनके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध और ऐसे चुनावों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों का निर्णय। आर. पी. अधिनियम, 1951 का भाग-VI चुनावों के संबंध में विवादों से संबंधित है और इसका अध्याय-II उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने से संबंधित है। इसकी धारा 80 में कहा गया है कि प्रश्नगत एनीमोजी करुणानिधि बनाम में कोई चुनाव नहीं बुलाया जाएगा।

ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत एक चुनाव याचिका द्वारा

कला-VII।

12. धारा 80 ए चुनाव पर मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। धारा 81 याचिकाओं की प्रस्तुति से संबंधित है जो इस प्रकार है:

देर:

" धारा 81। याचिकाओं की प्रस्तुति-(1) किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने वाली एक चुनाव याचिका धारा 100 और धारा 101 की [उप-धारा (1)] में निर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधारों पर उच्च न्यायालय में ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या किसी भी मतदाता द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

चुनाव अलग-अलग होते हैं, उन दोनों तिथियों के बाद।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा में, "निर्वाचक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिसके लिए चुनाव याचिका दायर की गई थी।

यह बताता है कि क्या उन्होंने ऐसे चुनाव में मतदान किया है या नहीं।

(2) [***]

[(3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उतने ही लोग होंगे

उसकी प्रतियाँ जैसा कि उत्तरदाताओं में उल्लिखित हैं

याचिका और ऐसी प्रत्येक प्रति को याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत याचिका की सही प्रति होने के लिए सत्यापित किया जाएगा।]

13. धारा 82 इस बारे में आदेश देती है कि याचिका के पक्षकार कौन होंगे। धारा 83 याचिका की सामग्री से संबंधित है, जो

निम्नानुसार:

83. याचिका की सामग्री-(1) एक चुनाव याचिका

(क) इसमें उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण देगा, जिसमें ऐसी भ्रष्ट प्रथा करने के लिए कथित पक्षों के नामों का यथासंभव पूरा बयान और ऐसी प्रत्येक प्रथा के आयोजन की तारीख और स्थान शामिल हैं; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा

अभिवचनों का सत्यापन:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है,

याचिका के साथ एक शपथ पत्र भी होगा इस तरह के भ्रष्ट आचरण के आरोप के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र

और उसके विवरण।]

(2) याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान ही सत्यापित किया जाएगा।]

14. धारा 86 के अनुसार, उच्च न्यायालय को उस याचिका को खारिज करने का अधिकार है जो धारा 81 की धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है। धारा 87 प्रक्रिया से संबंधित है

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया जो निम्नानुसार है:

" 87. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया।

(1) इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक चुनाव याचिका का मुकदमा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार, वाद के मुकदमे के लिए, जितना हो सके, किया जाएगा: बशर्ते कि उच्च न्यायालय को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी गवाह या गवाह से पूछताछ करने से इनकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि यह राय है कि ऐसे गवाह या गवाहों का साक्ष्य याचिका के निर्णय के लिए सामग्री नहीं है या कि ऐसा गवाह या गवाह पेश करने वाला पक्ष ऐसा कर रहा है।

तुच्छ आधार या कार्यवाही में देरी करने की दृष्टि से। (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभी मामलों में लागू माने जाएंगे।

एक चुनाव याचिका के मुकदमे का सम्मान करता है "।

15. जिन आधारों पर उच्च न्यायालय चुनाव से लौटे उम्मीदवार को अमान्य घोषित कर सकता है, वे धारा 100 में गिने गए हैं जो

निम्नानुसार:

100. चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आधार। - (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, यदि उच्च न्यायालय की राय है।

(अ)

(ख) -

(ग)-कनिमोझी करुणानिधि बनाम। ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

(घ) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक इसका संबंध है,

उम्मीदवार, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है

((i) -

((ख) -

((iii) -

((iv) संविधान के प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन द्वारा

या इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के, उच्च न्यायालय लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव की घोषणा करेगा -

खाली हो जाओ "।

16. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता ने अपीलार्थी के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी है कि चुनाव का परिणाम, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 324 के गैर-अनुपालन से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था और गैर-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम-4 ए का अनुपालन। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 33 नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन की आवश्यकताओं से संबंधित है। अनुभाग

36 निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकनों की जांच से संबंधित है। उसकी उप-धारा (2) निर्वाचन अधिकारी को किसी भी नामांकन पर की गई आपत्तियों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर उसमें उल्लिखित आधारों पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार करने का अधिकार देती है। नामांकन को अस्वीकार करने के आधारों में से एक है, जब धारा 33 के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता हुई हो। धारा 36 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो एक महत्वपूर्ण चरित्र का नहीं है।

17. चुनाव संचालन नियम, 1961 का भाग-II सामान्य प्रावधानों से संबंधित है। नियम-4 और नियम-4 ए जो नामांकन पत्र जमा करने और नामांकन पत्र देने के समय दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र के प्रपत्र से संबंधित है, जिसे नीचे पढ़ा गया है:

" 4. नामांकन पत्र-धारा 33 की उप-धारा (i) के तहत प्रस्तुत प्रत्येक नामांकन पत्र को ऐसे प्रपत्र 2 ए से 2 ई में से एक में पूरा किया जाएगा जो उपयुक्त हो:

बशर्ते कि फॉर्म 2 ए या फॉर्म 2 बी में नामांकन पत्र में प्रतीकों के बारे में घोषणा को पूरा करने में विफलता या पूरा करने में दोष को धारा 36 की उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर एक महत्वपूर्ण चरित्र का दोष नहीं माना जाएगा।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4 ए. नामांकन पत्र देने के समय दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र-उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र देने के समय,

उम्मीदवार द्वारा शपथ लिए गए एक शपथ पत्र को भी उसे सौंपें

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या फॉर्म 26 में नोटरी।

कानूनी स्थिति:

18. संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की योजना

आर. पी. अधिनियम में निर्वाचन के अधिकार की प्रकृति, निर्वाचित होने का अधिकार और निर्वाचन पर विवाद करने के अधिकार के संबंध में 1952 से विभिन्न संवैधानिक पीठों द्वारा व्याख्या और व्याख्या की गई है। ए का उल्लेख करने के लिए

कुछ एन. पी. पोन्नूस्वामी बनाम हैं। निर्वाचन अधिकारी, नामकल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य। ' , जगन नाथ बनाम जसवंत सिंह और अन्य। , भिकजी केशव जोशी और अन्न में। बनाम बृजलाल नंदलाल बियानी और Ors.7, मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौर और अन्य। आदि। 19. उक्त अधिकारियों से जो प्राप्त किया गया है, उसका सारांश यह कहते हुए किया जा सकता है कि चुनाव करने का अधिकार, हालांकि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है, न तो एक मौलिक अधिकार है और न ही एक सामान्य कानून अधिकार है। यह विशुद्ध रूप से एक वैधानिक अधिकार है। इसी तरह, निर्वाचित होने का अधिकार और चुनाव पर विवाद करने का अधिकार भी वैधानिक अधिकार हैं। चूंकि वे वैधानिक रचनाएँ हैं, वे वैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। चुनाव याचिका सामान्य कानून पर कार्यवाई नहीं है, न ही निष्पक्षता में। यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है जिसका उपयोग इसे बनाने वाले कानून के अनुसार किया जाना है। सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणा को तब तक चुनाव कानून के लिए अजनबी रहना चाहिए जब तक कि वैधानिक रूप से सन्निहित न हो। इस प्रकार, एक निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव करने के लिए बुलाने वाली अधिसूचना से जारी होने वाली पूरी चुनाव प्रक्रिया

चुनाव से संबंधित विवाद के अंतिम समाधान तक सदस्य या सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा विनियमित होते हैं। अतः उक्त आर. पी. अधिनियम को एक पूर्ण और स्व-निहित संहिता माना गया है जिसके भीतर चुनाव विवाद के संबंध में दावा किए गए किसी भी अधिकार को पाया जाना चाहिए। 20. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर 'के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण निर्णय में,

5 1952 (1) एससीसी 94

6 ए. आई. आर 1954 एस. सी 210

1 आकाशवाणी 1955 एससी 610

ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1545

- इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने एक सवाल उठाया-एक राष्ट्र में विवाहित और लोकतांत्रिक सरकार के रूप में, क्या मतदान करने से पहले, मतदाताओं को उनके बारे में प्रासंगिक विवरण जानने का अधिकार है। संसद या एस के विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने की तारीखें, संविधान की धारा 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों पर विचार-विमर्श किया गया और निम्नानुसार देखा गया:

" 46. उभरने वाली कानूनी और संवैधानिक स्थिति का सारांश

उपरोक्त चर्चा से यह कहा जा सकता है कि:

1. चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां शामिल हैं और

"चुनाव" शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसमें कई चरण होते हैं और शामिल होते हैं।

कई कदम।

2. शक्ति के पूर्ण स्वरूप की सीमा तब होती है जब संसद या राज्य विधानमंडल ने इससे संबंधित या उससे संबंधित एक वैध कानून बनाया हो।

चुनाव के संबंध में, आयोग को उक्त प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है। यदि कानून चुप रहता है, तो अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने की शक्ति का भंडार है। संविधान ने अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग के लिए गुंजाइश छोड़ने का ध्यान रखा है

एक बड़े लोकतंत्र में समय-समय पर उभरने वाली अनंत विविधता की स्थितियों में संविधान के एक प्राणी के रूप में अपने स्वयं के अधिकार में आयोग, क्योंकि प्रत्येक आकस्मिकता को अधिनियमित कानूनों या नियमों द्वारा पूर्वानुमेय या प्रत्याशित नहीं किया जा सकता था। आयोग आवश्यक निर्देश जारी करके वहां तक की कमी को पूरा कर सकता है

इस विषय पर कानून है। कन्ह्यालाल उमर मामले [(1985) 4 एस. सी. सी. 628] न्यायालय अनुच्छेद 324 (1) में "अधीक्षण, निर्देश आ नियंत्रण" पदों को व्याख्या कयलक आ अभिनिर्धारित कयलक जे कोनो निर्देशक अर्थ कोनो विशेष व्यक्तिकें जारी कयल गेल आदेश अथवा एकटा नियम भऽ सकैत अछि जकर पालन कतेको लोककें करय पड़ सकैत अछि आ ई एकटा विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश भऽ सकैत अछि आ एहन वाक्यांशक अर्थ उदारतापूर्वक चुनाव आयोगकें एहन आदेश जारी करबाक लेल सशक्त करैत बुझायल जा सकैत अछि।

3.

4. चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के लिए और विशेष रूप से चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग पूछ सकता है

राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च और चुनाव की प्रक्रिया में इस पारदर्शिता के बारे में उम्मीदवारों में शामिल होंगे [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चुनाव या पुनर्निर्वाचन चाहने वाले उम्मीदवार की पारदर्शिता में।

लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया की एक रणनीतिक भूमिका होती है। इस देश के छोटे आदमी को एक उम्मीदवार का पूरा विवरण जानने का बुनियादी प्राथमिक अधिकार होगा जो संसद में उसका प्रतिनिधित्व करेगा जहां उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति को बांधने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं।

21. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त नियमों में जोड़े गए नियम-4 ए और प्रपत्र-26 का सम्मिलन भी उक्त नियमों की परिणति है।

उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ, जिसमें उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र के रूप में जानकारी और विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।

22. प्रत्यर्थी-इस मामले में चुनाव याचिकाकर्ता ने उक्त नियम-4 ए और प्रपत्र-26 का पालन न करने के आधार पर धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत अपीलार्थी-लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी है। हालाँकि, अपीलार्थी ने खारिज करने के लिए आवेदन दायर किए थे

सी. पी. सी. के आदेश VII, नियम 11 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए सीमित रूप से चुनाव याचिका।

23. ई. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) की आवश्यकता के गैर-अनुपालन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अब तक विकसित और निपटाया गया कानून, अर्थात्-"एक चुनाव याचिका में एक संक्षिप्त बयान होना चाहिए -

याचिकाकर्ता जिन भौतिक तथ्यों पर भरोसा करता है, वह यह है कि ऐसा गैर-अनुपालन

आदेश VII, नियम 11, सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 83 (1) (ए) के तहत चुनाव याचिका को सीमा से ठीक पहले खारिज किया जा सकता है। " भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जो यदि स्थापित हो जाते हैं तो याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत मिल जाएगी। जिस परीक्षण का उत्तर दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या अदालत चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में सीधा फैसला दे सकती थी, यदि वापस लौटे उम्मीदवार याचिका में बताए गए तथ्यों के आधार पर चुनाव याचिका का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। वे ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए एक आधार प्रदान करेंगे और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में समझी गई कार्रवाई का कारण बनेंगे। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक कथन भी शामिल होगा।

24. हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी (उपरोक्त) मामले की तीन न्यायाधीशों की पीठ को आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) पर विचार करने का अवसर मिला और अदालत ने चुनाव याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह गंजा और अस्पष्ट है।

चुनाव याचिकाओं में किए गए कथन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं एनीमोजी करुणानिधि बनाम की धारा 83 (1) (ए) के अर्थ के भीतर "भौतिक तथ्यों" का अभिवचन करना।

ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]पी अधिनियम आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. की आवश्यकताओं के साथ पढ़ा जाता है। यह पैरा 23 और 24 में निम्नानुसार देखा गया है: -

" 23. आर. पी. ए., 1951 की धारा 83 (1) (ए) में आदेश दिया गया है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जिन भौतिक तथ्यों को बताए जाने की आवश्यकता है, वे हैं - वे तथ्य जिन्हें लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाली सामग्री माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों का आधार हों और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में समझी गई कार्रवाई का कारण हों। अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" को समग्र रूप से प्रत्येक तथ्य के अर्थ में परिभाषित किया गया है जिसे वादी के लिए अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि पार किया जाता है, तो साबित करना आवश्यक होगा। एक भौतिक तथ्य को छोड़ देने से कार्रवाई का एक अधूरा कारण बनता है और दावे का बयान गलत हो जाता है। पक्ष का कार्य इस तरह की आगे की जानकारी के साथ कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है।

विरोधी पक्ष को मामले को समझने के लिए वह क्या करेगा

मिलना पड़ता है। (सामंत एन. बालकृष्ण बनाम देखें। जॉर्ज

फर्नांडिस [(1969) 3 एस. सी. सी. 238: (1969) 3 एस. सी. आर. 603], जितेंद्र बहादुर सिंह बनाम। कृष्ण बिहारी [(1969) 2 एस. सी. सी. 433]। केवल किसी मंत्र के जाप जैसे खंड के शब्दों को उद्धृत करना भौतिक तथ्यों को बताने के बराबर नहीं है। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और यदि आवश्यक हो तो नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रतिपादन भी शामिल होगा। वी. एस. अच्युतानंदन बनाम पी. जे. फ्रांसिस [(1999) 3 एस. सी. सी. 737] इस न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला के संबंध में निर्णय दिया है कि भौतिक तथ्य ऐसे प्रारंभिक हैं।

तथ्य जो स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा मुकदमे में साबित किए जाने चाहिए

कार्रवाई के कारण का अस्तित्व। "भौतिक तथ्यों" की पैरवी करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और समय-सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने के लिए अभिवचनों में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं है।

निर्वाचन याचिका दाखिल करने के लिए विहित।

24. यह अदालत का कर्तव्य है कि वह याचिका की जांच करे, चाहे कोई भी हो।

यदि याचिका कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है तो किसी भी लिखित बयान या इनकार को अस्वीकार कर दें। अदालत को इस आधार पर किसी वाद को अस्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए कि वह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है, उसे वाद को देखना चाहिए और कुछ नहीं। अदालतों ने हमेशा अस्पष्ट दलीलों को अस्वीकार किया है जो किसी भी [2023] 4 एस. सी. आर. को जोड़ने के लिए एक व्यापक गुंजाइश छोड़ते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सबूत। सबूत की कोई भी मात्रा बुनियादी दोष को ठीक नहीं कर सकती है

दलीलें "। 25. महादेवराव सुकाजी शिवशंकर बनाम रामरतन के मामले में

& ओआरएस "।, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फिर से इन मुद्दों पर विचार करने के लिए एक आदेश दिया कि सामग्री 9 का गठन क्या होगा और निर्वाचन याचिका में "सामग्री" का उल्लेख नहीं करने के क्या परिणाम होंगे, जैसा कि सी. टी. की धारा 83 (1) (ए) में विचार किया गया है, और न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 6. अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी भौतिक तथ्यों को एक चुनाव याचिका में स्थापित किया जाना चाहिए। यदि किसी वाद या याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो उसे केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता है क्योंकि मामला संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) के दायरे में आएगा। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को निर्धारित किया था। अधिनियम में "भौतिक तथ्य" अभिव्यक्ति को न तो परिभाषित किया गया है। न ही कोड में। यह कहा जा सकता है कि भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन पर एक पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन पर वादी की कार्रवाई का कारण या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है। किन विवरणों को भौतिक तथ्य कहा जा सकता है, यह इन तथ्यों पर निर्भर करेगा -

प्रत्येक मामले और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य जो कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा मुकदमे में साबित किए जाने चाहिए, वे भौतिक तथ्य हैं और

पार्टी की दलील में कहा गया है।

7. लेकिन, यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि "भौतिक तथ्यों" और "विवरणों" के बीच अंतर है। भौतिक तथ्य प्राथमिक या बुनियादी तथ्य होते हैं जिनके समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिए

उसके द्वारा या तो अपनी कार्रवाई का कारण साबित करने के लिए स्थापित किया गया मामला या

रक्षा। दूसरी ओर, पक्ष द्वारा अनुरोध किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे बुनियादी तथ्यों को अंतिम रूप देकर भौतिक तथ्यों को बढ़ाते हैं, परिष्कृत करते हैं और सुशोभित करते हैं।

पहले से खींची गई तस्वीर की आकृति ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके। विशिष्टताएँ मेले के संचालन को सुनिश्चित करती हैं

मुकदमा चलाएंगे और विरोधी पक्ष को आश्चर्यचकित नहीं करेंगे। "

26. अनिल वासुदेव

सलगांवकर बनाम नरेश कुशाली

लेकिन इस अदालत ने पहले के कई फैसलों पर चर्चा की है (7) एससीसी 181

(9) एस. सी. सी. 310 एनीमोजी करुणानिधि बनाम। ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

मुकदमा करना कि चुनाव याचिका को कब संक्षिप्त रूप से खारिज किया जा सकता है या इसके तहत शक्तियों के प्रयोग में कार्रवाई का कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है

आर. पी. अधिनियम की धारा 83 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया।

" 50. स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है कि एक चुनाव याचिका को संक्षेप में खारिज किया जा सकता है यदि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत नहीं करती है।

संहिता के तहत शक्तियों के प्रयोग में उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं यदि अधिनियम की धारा 83 द्वारा चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को शामिल करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

इनका पालन नहीं किया जाता है। 51. सामंत एन. बालकृष्ण मामले [(1969) 3 एस. सी. सी. 238] में इस न्यायालय ने खुद को अनिश्चित शब्दों में व्यक्त किया है कि चूक

एक एकल भौतिक तथ्य के कारण कार्रवाई का एक अधूरा कारण होगा और यह कि एक भ्रष्ट प्रथा से संबंधित भौतिक तथ्यों के बिना एक चुनाव याचिका बिल्कुल भी चुनाव याचिका नहीं है। उधव सिंह बनाम। माधव राव सिंधिया [(1977) 1 एस. सी. सी. 511] कानून में कहा गया है कि सभी प्राथमिक तथ्य जो एक पक्ष द्वारा कार्रवाई के कारण या उसके बचाव को स्थापित करने के लिए साबित किए जाने चाहिए, वे सामग्री हैं।

तथ्य। भ्रष्ट आचरण के आरोप के संदर्भ में इसका अर्थ यह होगा कि मूल तथ्य जो याचिकाकर्ता द्वारा कथित विशेष भ्रष्ट आचरण के घटकों का गठन करते हैं, आरोप पर सफल होने के लिए निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। चाहे चुनाव याचिका में ए

विशेष तथ्य भौतिक है या नहीं और इस प्रकार अनुरोध करने की आवश्यकता लगाए गए आरोप की प्रकृति पर निर्भर करती है और

मामले की परिस्थितियाँ। कार्रवाई के पूर्ण कारण के साथ याचिका को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए और एक भी भौतिक तथ्य का अनुरोध करने में विफलता धारा 83 (1) (ए) के अधिदेश की अवज्ञा के बराबर होगी। इसलिए एक चुनाव याचिका खारिज की जा सकती है और उसे खारिज किया जाना चाहिए यदि वह ऐसी किसी बुराई से ग्रस्त है। इसलिए चुनौती का पहला आधार विफल होना चाहिए।

52. वी. नारायणस्वामी बनाम। सी. पी. थिरुनावुक्कारासु [(2000) 2 एस. सी. सी. 294] इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराया कि यदि कोई चुनाव याचिका भौतिक तथ्यों में नहीं है तो उसे खारिज किया जा सकता है। एल. आर. शिवरामगौड़ा बनाम टी. एम. चंद्रशेखर [(1999) 1 एस. सी. सी. 666] इस न्यायालय ने एक बार फिर दलीलों के महत्व पर विचार किया।

भ्रष्टाचार के दायरे में आने का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 123 का और निम्नानुसार अवलोकन किया गया: (एस. सी. सी. पी. 677 ,

पैरा 11)

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. इस न्यायालय ने बार-बार एक चुनाव याचिका में दलीलों के महत्व पर जोर दिया है और 'भौतिक तथ्यों' और 'भौतिक विवरणों' के बीच के अंतर को इंगित किया है। जबकि भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और अभिवचन के किसी भी संशोधन को चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भौतिक विवरणों की अनुपस्थिति को बाद के चरण में एक उचित संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है। "

53. उधव सिंह मामले [(1977) 1 एस. सी. सी. 511] में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पीपी। 522-23 , पैरा 41)

" 41. सिविल प्रक्रिया संहिता की तरह, यह धारा भी

'भौतिक तथ्यों' के बीच अंतर की परिकल्पना करता है और

भौतिक तथ्यों की कमी के कारण, कार्रवाई के कारण के अभाव में याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज किया जा सकता है। सामग्री विवरण की कमी से पीड़ित याचिका के मामले में, अदालत को याचिकाकर्ता को आवश्यक आपूर्ति करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है। सीमा की समाप्ति के बाद भी विवरण "।

54. एच. डी. रेवन्ना मामले में [(1999) 2 एस. सी. सी. 217] अपील उस उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी जो चुनाव में सफल रहा था और जिसका चुनाव याचिका को सीमित रूप से खारिज करने का आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय ने देखा कि इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि

यदि मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 और आदेश 7 नियम 11 के दायरे में आता है तो धारा 83 के प्रावधानों से याचिका खारिज हो सकती है। हरमोहिंदर सिंह में प्रधान बनाम. रंजीत सिंह तलवंडी [(2005) 5 एस. सी. सी. 46] इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एस. सी. सी पी. 51, पैरा 14)

इमोजी करुणानिधि बनाम। ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

" 14. मतदान करने के लिए 'उसके धर्म' के आधार पर अपील करने वाले तथ्यों का आवश्यक प्रतिपादन या मतदान से बचना खंड (ए) के अर्थ के भीतर भौतिक तथ्य होंगे। अधिनियम की धारा 83 की उप धारा (1)। यदि ऐसे भौतिक तथ्य गायब हैं, तो उन्हें बाद में प्रदान नहीं किया जा सकता है, चुनाव याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद और याचिका में कमी होने के कारण, निम्नलिखित के तहत रद्द करने का निर्देश दिया जा सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 6 नियम 16 और यदि ऐसी याचिका चुनाव याचिका दायर करने का एकमात्र आधार है, तो याचिका को ही खारिज किया जा सकता है क्योंकि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है।

संहिता के नियम 11, आदेश 7 के खंड (ए) के तहत।

3. हरकीरत सिंह बनाम। अमरिंदर सिंह [(2005) 13 एस. सी. सी. 511] अदालत ने फिर से "भौतिक तथ्यों" डी "भौतिक विवरणों" के बीच अंतर को दोहराया और निम्नानुसार देखा: (एस. सी. सी. पी. 527 , रास 51-52)

" 51. 'भौतिक तथ्य' और 'विशेष' के बीच का अंतर,

हालाँकि, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ' भौतिक तथ्य 'प्राथमिक या बुनियादी तथ्य होते हैं जिन्हें साबित करने के लिए वादी या प्रतिवादी द्वारा उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में अनुरोध किया जाना चाहिए।

उसकी कार्रवाई या बचाव का कारण। ' दूसरी ओर, 'विवरण' पक्ष द्वारा अनुरोध किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे पहले से ही एक चित्र की मूल रूपरेखा को विशिष्ट स्पर्श देकर भौतिक तथ्यों को बढ़ाते हैं, परिष्कृत करते हैं और सुशोभित करते हैं। इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रकार 'विवरण' निष्पक्ष सुनवाई के संचालन को सुनिश्चित करते हैं और नहीं करेंगे

विरोधी पक्ष को आश्चर्यचकित करें। 52. पक्ष द्वारा उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में सभी 'भौतिक तथ्यों' का अनुरोध किया जाना चाहिए। चूंकि इसका उद्देश्य और उद्देश्य विरोधी पक्ष को उस मामले को जानने में सक्षम बनाना है जिससे उसे मिलना है, इसलिए अभिवचन के अभाव में, किसी पक्ष को साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, एक भी भौतिक तथ्य बताने में विफल रहने पर वाद या याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, विशेष मामले का विवरण है जो प्रकृति में है

सबूत एक पक्ष मुकदमे के समय नेतृत्व करेगा।

5. सुदर्शन अवस्थी बनाम। शिव पाल सिंह [(2008) 7 एस. सी. सी. 604] का न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है: (एस. सी. सी. पी. 612, पैरा 20)

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 20. चुनाव याचिका एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में या काल्पनिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है और न ही इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसे परेशान करने वाले उद्देश्य के लिए एक हेंडल के रूप में उपयोग करता है।

57. यह तय कानूनी स्थिति है कि सीमा की अवधि के भीतर पक्ष द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में सभी "भौतिक तथ्यों" का अनुरोध किया जाना चाहिए। चूंकि इसका उद्देश्य और उद्देश्य विरोधी पक्ष को उस मामले को जानने में सक्षम बनाना है जिससे उसे मिलना है, इसलिए अभिवचन के अभाव में, किसी पक्ष को साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक भी भौतिक तथ्य बताने में विफल रहने पर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। चुनाव याचिका में "भौतिक तथ्यों" का एक संक्षिप्त बयान होना चाहिए जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और न ही नागरिक संहिता में प्रक्रिया। निर्णयों की एक श्रृंखला में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि कार्रवाई के पूर्ण कारण को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों को

इसे "भौतिक तथ्य" कहा जा सकता है। कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य भौतिक तथ्य हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक तथ्यों का अर्थ है तथ्यों का पूरा बंडल जो कार्रवाई का एक पूर्ण कारण होगा। हरकीरत सिंह में यह अदालत मामला [(2005) 13 एस. सी. सी. 511] ने "भौतिक तथ्यों" के विभिन्न अर्थ देने का प्रयास किया। उक्त निर्णय का सुसंगत पैरा 48 है -

निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया: (एससीसी पीपी। 526-27)

" 48. 'भौतिक तथ्य' शब्द को न तो अधिनियम में परिभाषित किया गया है और न ही संहिता में। शब्दकोश के अर्थ के अनुसार, 'सामग्री' का अर्थ है 'मौलिक', 'महत्वपूर्ण', 'बुनियादी', 'कार्डिनल', 'केंद्रीय', 'महत्वपूर्ण', 'निर्णायक', 'आवश्यक', 'महत्वपूर्ण', 'अपरिहार्य', 'प्राथमिक' या 'प्राथमिक'। [बर्टन का कानूनी थीसॉरस (तीसरा संस्करण), पी। 349.] अतः 'भौतिक तथ्य' वाक्यांश को वे तथ्य कहा जा सकता है जिन पर एक पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, 'भौतिक तथ्य'

वे तथ्य हैं जिन पर वादी की कार्रवाई का कारण या

प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है। किन विवरणों को 'भौतिक तथ्य' कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा मुकदमे में साबित किए जाने वाले सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य भौतिक तथ्य हैं।

और पक्ष द्वारा अभिवचन में कहा जाना चाहिए। कनिमोजी करुणानिधि बनाम।

ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

27. राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने आर. पी. अधिनियम की धारा 0 (1) (डी) (iv) के तहत दायर चुनाव याचिका की स्थिरता की फिर से जांच की, जिसमें पहले के फैसलों पर विस्तार से विचार किया गया था।

डी ने पाया कि चुनाव याचिकाकर्ता के लिए यह आवश्यक था कि वह

ई. सी. आई. सी. किस तरह से चुनाव का परिणाम अब तक

रिटनिंग ऑफिसर के हिस्से को छोड़ने के कारण लौटने वाला उम्मीदवार भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। उक्त मामले में न्यायालय ने यह मानते हुए कि चुनाव याचिका में इस तरह के कथन गायब हैं, उच्च न्यायालय/चुनाव न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें सीमा पर चुनाव को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने पैरा 14 से 21 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 14. अधिनियम की धारा 81, 83 और 86 के संदर्भ में भौतिक तथ्यों के बयान और इस तरह के प्रकटीकरण की कमी के परिणामों के बारे में एक चुनाव याचिका में आवश्यकता सामंत एन बालकृष्ण बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आई। जॉर्ज फर्नांडिस [(1969) 3 एस. सी. सी. 238]। तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, एम. हिदायतुल्ला, सी. जे. ने अन्य बातों के साथ कहा कि:

(i) अधिनियम की धारा 83 अनिवार्य है और इसके लिए पहले भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और फिर पूर्ण संभव विवरण की आवश्यकता होती है।

((ii) एक भी भौतिक तथ्य को छोड़ देने से एक अपूर्ण तथ्य सामने आता है।

कार्रवाई का कारण और दावे का बयान खराब हो जाता है;

((ग) विवरण का कार्य कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना और विरोधी पक्ष को उस मामले को समझाना है जिससे उसे मिलना है।

((iv) भौतिक तथ्य और विवरण अलग-अलग मामले हैं-भौतिक तथ्य तथ्य के बयानों का उल्लेख करेंगे और विवरण तारीख, समय और स्थान के साथ व्यक्तियों के नाम निर्धारित करेंगे; और

(v) भौतिक तथ्यों को बताने में केवल खंड के शब्दों को उद्धृत करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि तब भौतिक तथ्यों की प्रभावकारिता समाप्त हो जाएगी।

15. इस मोड़ पर, "भौतिक तथ्य" वाक्यांश के वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य को समझने के लिए, विशेष रूप से चुनाव कानून के संदर्भ में, खंड (ए) में दिखाई देने वाले "भौतिक तथ्य" और [2023] 4 एस. सी. आर. की उप-धारा (1) के खंड (बी) में दिखाई देने वाले "विवरण" वाक्यांशों के बीच के अंतर पर ध्यान देना उचित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 83। जैसा कि ऊपर कहा गया है, "भौतिक तथ्य" प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा अपने कारण को साबित करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

कार्रवाई की और प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव साबित करने के लिए। दूसरी ओर, "विवरण", पक्षों द्वारा अनुरोध किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे सामग्री को बढ़ाते हैं, परिष्कृत करते हैं और सजाते हैं।

पहले से खींची गई तस्वीर की मूल रूपरेखा को विशिष्ट स्पर्श देकर तथ्य ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक बनाया जा सके।

सूचनात्मक। "भौतिक तथ्यों" के विपरीत जो मूल आधार प्रदान करते हैं जिस पर चुनाव याचिका की पूरी इमारत बनाई गई है, "विवरण" यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि इसके विपरीत पार्टी आश्चर्यचकित नहीं होती है।

16. "भौतिक तथ्य" और "विवरण" के बीच का अंतर

और एक चुनाव याचिका में उनकी आवश्यकता को इस न्यायालय द्वारा विरेंद्र नाथ गौतम बनाम में संक्षिप्त रूप से सामने लाया गया था। सतपाल

सिंह [(2007) 3 एस. सी. सी. 617] जिसमें सी. के. ठक्कर, जे. ने इस प्रकार कहा: (एससीसी पीपी। 631-32 , पैरा 50) " 50. तथ्य प्रोबान्डा (साबित करने के लिए आवश्यक तथ्य यानी भौतिक तथ्य) और तथ्य प्रोबान्टिया (जिन तथ्यों के माध्यम से वे साबित होते हैं यानी विवरण या तथ्य) के बीच अंतर होता है।

सबूत)। यह तय किया गया कानून है कि अभिवचनों में केवल तथ्य प्रोबंडा होना चाहिए न कि तथ्य प्रोबेंटिया। जिन भौतिक तथ्यों पर

पार्टी अपने दावे के लिए निर्भर करती है जिसे तथ्य रोबान्डा कहा जाता है और उन्हें अभिवचनों में कहा जाना चाहिए। लेकिन जिन तथ्यों या तथ्यों के माध्यम से तथ्य प्रोबंडा (भौतिक तथ्य) साबित होते हैं और जो तथ्य प्रोबेंटिया (विवरण या साक्ष्य) की प्रकृति में होते हैं, उन्हें अभिवचनों में निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। वे मुद्दे में तथ्य नहीं हैं, बल्कि मुद्दे में तथ्य को स्थापित करने के लिए मुकदमे में केवल प्रासंगिक तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता है।

17. अब, विवादित कानूनी स्थिति के आलोक में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की जांच करने से पहले, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के एक और प्रस्तुतिकरण पर विचार करना समीचीन होगा कि उच्च न्यायालय को सीमा पर चुनाव याचिका को अस्वीकार करने के लिए संहिता के आदेश 6 नियम 16 या आदेश 7 नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तर्क दो गुना है। : (i) कि भले ही चुनाव याचिका अंततः खारिज होने के लिए उत्तरदायी थी, लेकिन इसे चुनाव याचिकाकर्ता को याचिका में अपने आरोप के समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर देने के बाद ही खारिज किया जाना चाहिए था, और एनीमोजी करुणानिधि V.

ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

(ii) चूंकि धारा 83 को अधिनियम की धारा 86 में कोई स्थान नहीं मिलता है, इसलिए याचिका को सीमा पर अस्वीकार करना धारा 86 की उप-धारा (1) को एक अतिरिक्त आधार में पढ़ने के बराबर होगा। हमारी राय में, दोनों विवाद गलत धारणा वाले और असमर्थनीय हैं।

18. निस्संदेह, अधिनियम की धारा 87 के आधार पर, संहिता के प्रावधान एक चुनाव याचिका के मुकदमे पर लागू होते हैं और इसलिए, अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी नहीं होने पर, चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाला न्यायालय संहिता के आदेश 6 नियम 16 और आदेश 7 नियम 11 सहित संहिता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

अर्थहीन मुकदमेबाजी, जो अन्यथा निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, को अदालतों के न्यायिक समय पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि सामान्य दीवानी मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में ऐसा है, तो इसे चुनाव मामलों में अधिक जोर-शोर से लागू होना चाहिए, जहां एक चुनाव याचिका के लंबित होने से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा आने की संभावना है, जिसके लिए मतदाताओं ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए प्रस्तुतिकरण असफल होना चाहिए।

19. तर्क के दूसरे अंग पर आते हैं। अधिनियम की धारा 86 में धारा 83 की अनुपस्थिति, जो विशेष रूप से प्रदान करती है

एक चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए जो अनुपालन नहीं करती है

अधिनियम के कुछ प्रावधान, हमारे विचार में, मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। इसी तरह की याचिका को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हरद्वारी लाल बनाम में खारिज कर दिया था। कंवल सिंह [(1972) 1 एस. सी. सी. 214], जिसमें पीठ की ओर से बोलते हुए, ए. एन. रे, जे. (तब उनके स्वामी के रूप में) ने कहा: (एस. सी. सी. पी. 221, पैरा 23)

उच्च न्यायालय ने उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जो अधिनियम की धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती थी। इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 83 को धारा 86 में जगह नहीं मिली। अधिनियम की धारा 87 के तहत प्रत्येक चुनाव याचिका उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमों के मुकदमे के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार जितना हो सके, मुकदमा चलाया जाएगा। एक मुकदमा जो कार्रवाई का कारण प्रस्तुत नहीं करता है उसे खारिज किया जा सकता है। "[2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हुसैन बनाम। राजीव गांधी [1986 एस. सी. सी. 325]। सामंत एन. में इस न्यायालय की पूर्व घोषणाओं का उल्लेख करते हुए। बालकृष्ण [(1969) 3 एस. सी. सी. 238] और उद्धव सिंह बनाम। माधव राव सिंधिया [(1977) 1 एस. सी. सी. 511] जिसमें यह कहा गया था कि एक भौतिक तथ्य को छोड़ने से कार्रवाई का अधूरा कारण बन जाएगा और भौतिक तथ्यों के बिना एक चुनाव याचिका बिल्कुल भी चुनाव याचिका नहीं है, अजहर हुसैन मामले में पीठ ने कहा कि सभी तथ्य जो हैं

इस तरह के किसी भी बुराई से पीड़ित है।
कर सकते हैं कि क्या

21. अब हम यह जांचने के लिए तथ्यों का विज्ञापन

चुनाव याचिका को अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) में निर्धारित भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि चुनाव याचिकाकर्ता का मामला धारा 100 (1) (डी) (iv) के कथित उल्लंघन तक सीमित है। तैयार संदर्भ के लिए, उक्त प्रावधान नीचे निकाला गया है:

(1) उप-धारा के प्रावधानों के अधीन

(2) यदि उच्च न्यायालय की राय है

(घ) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक एक लौटे हुए उम्मीदवार की बात है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

((iv) संविधान के प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन द्वारा

या इस अधिनियम के या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के,

उच्च न्यायालय लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करेगा। यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान के तहत एक चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए, चुनाव याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान या इस अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन न करने के कारण, ओज़ी करूणानिधि V.

ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

जहां तक लौटने वाले उम्मीदवार का संबंध है, कार्रवाई बहुत प्रभावित हुई थी। वह पूर्व-वर्णित मामलों में उल्लिखित कानूनी स्थिति हो सकती है -

निम्नानुसार:

याचिका में लगाए गए आरोपों का आधार और कार्रवाई के कारण का गठन करता है, वह प्रत्येक तथ्य है जिसे वादी/याचिकाकर्ता के लिए साबित करना आवश्यक होगा, यदि इसके निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए पार किया जाता है।

अदालत। एकल भौतिक तथ्य को छोड़ देने से कार्रवाई का एक अधूरा कारण होगा और शिकायत का बयान होगा

खराब हो जाता है।

भौतिक तथ्यों का अर्थ है तथ्यों का पूरा समूह जो कार्रवाई का एक पूर्ण कारण होगा। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और यदि आवश्यक हो तो नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रतिपादन भी शामिल होगा। आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत एक चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए, चुनाव याचिकाकर्ता को प्रावधानों का पालन न करने के कारण इस बात से बचना चाहिए कि

संविधान या अधिनियम या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अनुसार, चुनाव का परिणाम, जहां तक वापस लौटे उम्मीदवार का संबंध है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था।

चुनाव याचिका एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में या काल्पनिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है और न ही इसे किसी को दिया जाता है।

व्यक्ति जो इसे परेशान करने वाले उद्देश्य के लिए एक हैंडल के रूप में उपयोग करता है।

एक चुनाव याचिका को संक्षेप में खारिज किया जा सकता है

एक एकल भौतिक तथ्य को छोड़ना जो एक अपूर्ण तथ्य की ओर ले जाता है कार्रवाई का कारण, या भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त बयान शामिल करने में चूक, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है

[2023] 4 एस. सी. आर. की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई का कारण स्थापित करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश VII सी. पी. सी. के नियम 11 के खंड (ए) के तहत धारा 83 द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ पढ़ा जाता है

आर. पी. अधिनियम।

निष्कर्ष:

29. ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति के आलोक में, आइए देखें कि क्या प्रतिवादी/चुनाव याचिकाकर्ता ने आवश्यकताओं का पालन किया था

आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (ए), चुनाव याचिका में "भौतिक तथ्यों" को बताते हुए, कार्रवाई का कारण और आधार के रूप में

आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) में विचार किया गया है, ताकि अपीलार्थी द्वारा वापस किए गए उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित किया जा सके। की हड्डी

प्रत्यर्थी चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि भारत के चुनाव आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों के आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति के संबंध में फॉर्म 26 निर्धारित करने वाली जानकारी मांगी थी और इसमें कहा गया था कि

याचिकाकर्ता ने जानकारी दी थी कि उसका जीवनसाथी विदेश में सलाहकार के रूप में काम कर रहा था और फॉर्म 26 के भाग ए के तहत क्रमशः columnNo.8, सीरियल नंबर 9 (बी) और 9 ए (बी) के बदले वेतन अर्जित कर रहा था। इसके अलावा, उन्होंने अपने जीवनसाथी के आयकर बकाया (तमिल भाषा में "एथुमिलाई" के रूप में उल्लिखित) के बारे में पूछे गए प्रश्न के लिए "नहीं" का उल्लेख किया था। उसने आगे कहा था कि उसकी पत्नी के बैंक खाते सिंगापुर में जमा थे। फॉर्म 26 के भाग ए में कॉलम के कॉलम नंबर 7 सीरियल नंबर (ii) के खिलाफ डॉलर, लेकिन विदेश में अपने जीवनसाथी की आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का खुलासा करने में विफल रही थी। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये सामग्री

तथ्य जो चुनाव याचिका में पहले ही बताए जा चुके हैं, आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। 30. यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्यर्थी चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपनी चुनाव याचिका के पैरा 5 से 9 में लगाए गए सटीक आरोप पहले ही लगाए जा चुके हैं।

यहाँ पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि चुनाव याचिकाकर्ता यानी प्रतिवादी ने भारत के संविधान या संविधान के किसी भी प्रावधान का अनुपालन कैसे नहीं किया गया, इस बारे में भौतिक तथ्यों को बताए बिना बहुत गंजे और अस्पष्ट आरोप लगाए हैं। आर. पी. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम। यदि चुनाव याचिका में किए गए कथनों को फॉर्म संख्या 26 में अपीलार्थी-लौटे उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अपीलार्थी के जीवनसाथी के पैन संख्या के बारे में मांगी गई जानकारी के खिलाफ, यह कहा गया है कि "कोई पैन संख्या नहीं", "पति/पत्नी के।

कनिमोझी करुणानिधि बनाम। ए. शांतना कुमार [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अरविंदन विदेशी नागरिकता "। "जिस वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम आयकर विवरणी दाखिल की गई है" के संबंध में मांगी गई जानकारी के विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपने जीवनसाथी के बारे में दी गई जानकारी है -

" लागू नहीं "। अपीलार्थी ने अपने स्थायी खाता संख्या और आयकर विवरणी आदि दाखिल करने की स्थिति आदि और जहां भी लागू हो, अपने पति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करके प्रपत्र संख्या 26 के सभी कॉलम भर दिए हैं। यदि प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता-लौटे उम्मीदवार ने अपने जीवनसाथी की स्थायी खाता संख्या को दबा दिया था और विदेश में अपने जीवनसाथी के आयकर का भुगतान न करने के बारे में भी, तो चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से यह बताना अनिवार्य था कि भारत में लौटे उम्मीदवार के जीवनसाथी की स्थायी खाता संख्या क्या थी, जिसे उसने दबा दिया था और कैसे उक्त प्रपत्र संख्या 26 में उसके पति के बारे में दिए गए अन्य विवरण अधूरे या झूठे थे।

31. बिना किसी आधार के केवल गंजे और अस्पष्ट आरोप भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा।

चुनाव याचिका। न केवल तथ्यों का सकारात्मक कथन, बल्कि नकारात्मक तथ्य का एक सकारात्मक कथन भी कहा जाना आवश्यक है, क्योंकि यह कार्रवाई के कारण का गठन करने वाला एक भौतिक तथ्य होगा। भौतिक तथ्य जो प्राथमिक और बुनियादी तथ्य हैं, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपने कारण को दिखाने के लिए उनके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में अनुरोध किया जाना चाहिए।

कार्रवाई और एक भी भौतिक तथ्य को छोड़ने से कार्रवाई का एक अधूरा कारण होगा, जिससे लौटे उम्मीदवार को आरपी अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) के साथ पठित आदेश VII नियम 11 (ए) सीपीसी के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार होगा। 32. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नामांकन पत्र के साथ फॉर्म 26 में एक हलफनामा उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उक्त अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 4 ए के अनुसार। निर्वाचन अधिकारी को या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर किसी भी नामांकनकर्ता को की गई आपत्तियों पर, धारा 36 (2) में उल्लिखित आधारों पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसमें इस आधार पर भी शामिल है कि अधिनियम की धारा 33 के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता हुई है। हालांकि, नामांकन पत्र की जांच और अपीलार्थी-लौटे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 26 में हलफनामे के समय, न तो कोई आपत्ति उठाई गई थी, न ही निर्वाचन अधिकारी ने नियमों की धारा 33 या नियम 4 ए का कोई चूक या गैर-अनुपालन पाया था।

यह मानते हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता के पास अपीलार्थी द्वारा भरे गए फॉर्म संख्या 26 को देखने का अवसर नहीं था, जब वह [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

100 (1) (घ) उक्त अधिनियम के (iv), तब भी आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत कार्रवाई के कारण का गठन करने वाली याचिका में कोई भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं। कार्रवाई का कारण बनने वाले भौतिक तथ्यों के अभाव में उक्त अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए, चुनाव याचिका को आदेश VII नियम के तहत खारिज करने की आवश्यकता है।

11 (क) आर. पी. अधिनियम की धारा 13 (1) (क) के साथ पठित सी. पी. सी.।

33. जैसा कि पहले विस्तार से चर्चा की गई है, आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) में आदेश दिया गया है कि एक चुनाव याचिका में एक संक्षिप्त बयान होगा -

भौतिक तथ्य जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है, और कौन से तथ्य कार्रवाई का कारण बनते हैं। इस तरह के तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रतिपादन भी शामिल होगा। एक एकल तथ्य को छोड़ देने से कार्रवाई का अधूरा कारण बन जाएगा। जहाँ तक वर्तमान याचिका का संबंध है, इस बारे में कोई दावा नहीं किया गया है कि संविधान या आर. पी. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेश के प्रावधानों का अनुपालन कैसे नहीं किया गया और इस तरह का अनुपालन कैसे नहीं किया गया।

चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था, ताकि चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत आधार आकर्षित किया जा सके। इस तरह के महत्वपूर्ण और बुनियादी तथ्यों को बताने में चूक ने याचिका को आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 83 (आई) (ए) के साथ पठित आदेश VII, नियम 11 (ए) सीपीसी के तहत खारिज करने के लिए उत्तरदायी बना दिया है।

34. मामले के उस दृष्टिकोण से, चुनाव याचिका नहीं है। 3/2019 प्रत्यर्थी द्वारा दायर-चुनाव याचिकाकर्ता खारिज किए जाने के योग्य है, और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

35. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे (सहायक: भव्यता कपूर और रूपांशी विरंग, एलसीआरएएस)